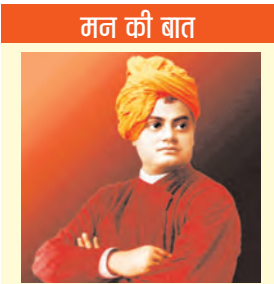




आगामी योग दिवस को लेकर देशभर में कार्यक्रम शुरू, मेघालय के लिविंग ब्रिज पर किया योग।



कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। - भगवत गीता



सब कुछ खोने से ज्यादा बुरा उस उम्मीद को खो देना जिसके भरोसे हम सब कुछ वापस पा सकते हैं। - स्वामी विवेकानंद

सेबी हितों के टकराव पर उच्चस्तरीय समिति करेगा गठित

टीम एक्शन इंडिया नई दिल्ली/मुंबई। भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने सोमवार को निदेशक मंडल के सदस्यों और अधिकारियों के हितों के टकराव, संपत्ति, निवेश और देनदारियों से संबंधित खुलासे की व्यापक समीक्षा करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने का फैसला किया है। पूंजी बाजार नियामक सेबी के नवनिर्भूत चेयरमैन तुहिन कांत पांडेय ने निदेशक मंडल की यहां हुई बैठक में लिए गए फैसले की जानकारी मीडिया को दी। पांडेय ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सेबी मुख्य कार्यकारी अधिकारी सहित कर्मचारियों के हितों के टकराव और संबंधित मामलों के प्रबंधन के लिए मौजूदा ढांचे को बेहतर बनाने के लिए व्यापक समीक्षा करना और सफाई करना भी है, ताकि निवेशकों के सदस्यों और अधिकारियों के पारदर्शिता, जवाबदेही और नैतिक आवरण के उच्च मानक सुनिश्चित किए जा सकें।

चार वर्षों में 90 लाख से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए



टीम एक्शन इंडिया नई दिल्ली। आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने वालों ने पिछले चार वर्षों में 90 लाख से अधिक अपडेटेड आईटीआर-यू दाखिल किए गए। इससे सरकार को 9,118 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आमदनी हुई है। चालू वित्त वर्ष 2024-25 में 28 फरवरी तक 4.64 लाख अपडेटेड आईटीआर दाखिल किए

दाखिल किए

► चालू वित्त वर्ष 2024-25 में 28 फरवरी तक 4.64 लाख अपडेटेड आईटीआर दाखिल किए

के खजाने में 9,118 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। केंद्रीय मंत्री मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 में 29.79 लाख से अधिक अपडेटेड आईटीआर दाखिल किए गए और 2,947 करोड़ रुपये के अतिरिक्त कर का भुगतान हुआ। इसी तरह वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2021-22 में क्रमशः 40.07 लाख और 17.24 लाख अपडेटेड आईटीआर दाखिल किए गए, जिन्हें अतिरिक्त 3,940 करोड़ रुपये और 1,799.76 करोड़ रुपये के टैक्स प्राप्त हुए। उन्होंने सदन को बताया कि वित्त विधेयक, 2025 के माध्यम से सरकार ने अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने की समय-सीमा को संबंधित मूल्यांकन वर्ष से 4 साल तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है।

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

एक्शन इंडिया

वर्ष: 14 अंक: 81 पृष्ठ: 08

actionindiauna@gmail.com

हिमाचल संस्करण

दिल्ली - हरियाणा - हिमाचल प्रदेश - उत्तराखण्ड

RNI : HPHIN/2012/48072



मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर राज्यसभा में हंगामा

कर्नाटक में मुसलमानों को सार्वजनिक ठेकों में चार प्रतिशत आरक्षण देने के मुद्दे पर राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ, कांग्रेस से मांगा जवाब

हंगामा किया

► रिजिजू ने डीके शिवकुमार के संविधान पर दिए गए कथित बयान पर खरगो से जवाब मांगा

टीम एक्शन इंडिया नई दिल्ली। कर्नाटक में मुसलमानों को सार्वजनिक ठेकों में चार प्रतिशत आरक्षण देने के मुद्दे पर राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। सदन की कार्यवाही तीन बार स्थगित किए जाने के बावजूद बार-बार हो रहे व्यवधान के कारण मंगलवार पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। पूर्वाह्न 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सत्तापक्ष के सदस्यों ने हमला शुरू कर दिया। इस बीच संसदीय कार्यमंत्री किरें रिजिजू ने कर्नाटक के



किरेन रिजिजू ने मुस्लिम आरक्षण पर लोकसभा में कांग्रेस को घेरा

टीम एक्शन इंडिया नई दिल्ली। संसदीय कार्यमंत्री किरें रिजिजू ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के मुस्लिम आरक्षण पर

उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के संविधान पर दिए गए कथित बयान पर नेता विपक्ष एवं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से जवाब

दिए बयान का मुद्दा सोमवार को लोकसभा में उठाया। उन्होंने नाम लिए बिना कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का धर्म के आधार पर आरक्षण और उसके लिए संविधान बदलने की

मांगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संविधान को बदलना चाहती है। नेता सदन जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि

कांग्रेस अपना विवेक भी खो बैठी है: नड्डा

नड्डा ने कहा कि इन्होंने मुसलमानों को ओबीसी आरक्षण में बैक डोर से पंटी देने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि अब नौकरी तो छोड़िए, ठेकेदारी में भी आरक्षण होगा...। सत्ता से बाहर रहकर कांग्रेस अपना विवेक भी खो बैठी है। नड्डा के इस बयान का विपक्षी सदस्यों ने तीखा विरोध करते हुए शोरगुल और हंगामा किया, जिस पर उप सभापति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी। उसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही जब तीसरी बार शुरू हुई तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने विपक्ष की नारेबाजी के बीच तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक, 2024 में लोकसभा द्वारा किए गए संशोधनों को विचार के लिए पेश किया।

बात कहना असंभव है। यह संविधान निमाताओं का अपमान है। लोकसभा की कार्यवाही पहले विपक्षी सदस्यों के पोस्टर लेकर सदन में आने के कारण स्थगित हुई। लोकसभा

कर्नाटक में सार्वजनिक ठेकों में मुसलमानों को चार प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव पारित हुआ है। ये असंवैधानिक है।

बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाया तुष्टीकरण का आरोप

टीम एक्शन इंडिया नई दिल्ली। कर्नाटक में मुसलमानों को सरकारी ठेके में चार प्रतिशत आरक्षण देने के प्रस्ताव के मामले पर राजनीति गरमाती जा रही है। इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर हमले तेज करते हुए पार्टी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। सोमवार को भाजपा मुख्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि हम संविधान को बदलना चाहते हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस द्वारा एक पूरी तरह से झूठा और भ्रामक अभियान चलाया गया था कि अगर भाजपा को बहुमत या

400 सीटें मिलती हैं, तो वे संविधान को बदल देंगे। हमने बार-बार कहा कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे और हमने ऐसा नहीं किया। हमने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के लिए केवल एक बार संविधान में बदलाव किया, जिसकी सभी ने सराहना की। आज देश में बड़ा सवाल यह उभर रहा है कि वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति और मुस्लिम वोटों की खातिर देश किस ओर जा रहा है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस ने वोट बैंक की खातिर शाहबाजों पर आए फैसले को भी पलट दिया था।

विपक्षी दलों का यूजीसी

ड्राफ्ट के खिलाफ प्रदर्शन



टीम एक्शन इंडिया नई दिल्ली। आईएनडीआई गठबंधन के घटक दलों के छात्र संगठनों ने सोमवार को जंतर-मंतर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति और यूजीसी ड्राफ्ट सहित देश की शिक्षा व्यवस्था से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विरोध-प्रदर्शन किया। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने प्रदर्शन में भाग लेते हुए आरोप लगाया कि शैक्षणिक संस्थानों पर आज सत्ता पक्ष के लोग कब्जा कर रहे हैं। छात्रों के साथ भेदभाव किया जा रहा है और पेपर लीक जैसी घटनाएं हो रही हैं। विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के छात्र संगठन नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई), वाम दलों के छात्र संगठन अखिल भारतीय स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आईसा), स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई), ऑल

साधा निशाना

► प्रदर्शन में भाग लेते हुए आरोप लगाया कि शैक्षणिक संस्थानों पर आज सत्ता पक्ष के लोग कब्जा कर रहे

इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन (एआईएसएफ), मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन (एमएसएफ), समाजवादी छात्र सभा और छात्र राष्ट्रीय जनता दाल (सीआरजेडी) और अन्य संगठनों भाग लिया। राहुल ने जंतर-मंतर पर छात्र संगठनों के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के चलते किसी को रोजगार नहीं मिलेगा। देश बर्बाद हो जाएगा। आज विपक्ष की मांग को अनसुना किया जा रहा है।

पीएमजी ने बिहार, ओडिशा और बांगाल में ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की

टीम एक्शन इंडिया नई दिल्ली। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी) ने बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की व्यापक समीक्षा की है। इसके तहत 63,858 करोड़ रुपये की 19 प्रमुख परियोजनाओं



के 23 मुद्दों की समीक्षा की है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के

जिनमें कुल निवेश 63,858 करोड़ रुपये से अधिक है। इसमें श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत आने वाली पांच परियोजनाएं शामिल हैं, जो विशेष रूप से इन तीनों राज्यों में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) अस्पतालों पर केंद्रित हैं। इन अस्पतालों का उद्देश्य बीमा क्राए हुए नागरिकों और उनके परिवारों के लिए विशेष उपचार, दवाइयां और अस्पताल में

भत्ती सहित आवश्यक स्वास्थ्य सेवा लाभ प्रदान करना है। इसके अलावा इस्पात, कोयला, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, रेलवे और बिजली मंत्रालयों से संबंधित परियोजनाओं की समीक्षा की गई, ताकि बाधाओं की पहचान की जा सके और उन्हें दूर किया जा सके और साथ ही उनका सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके।

चीफ जस्टिस ने सभी सामग्री सार्वजनिक डोमेन में रखी : धनखड़

टीम एक्शन इंडिया नई दिल्ली। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने न्यायिक जवाबदेही और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेसी) के मुद्दे पर सोमवार को संसद भवन स्थित अपने कक्ष में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा और विपक्ष के नेता

मल्लिकार्जुन खरगे के साथ बैठक की। इस दौरान सभापति ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के उस निर्णय की सराहना की जिसमें उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के आवास से कथित तौर पर नकदी मिलने से संबंधित महत्वपूर्ण



दस्तावेजों को सार्वजनिक करने तथा मामले की तुलना में 250-300 रुपये प्रति किलोग्राम का प्रीमियम मूल्य मिले, जिससे जीआई टैगिंग और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आर्थिक लाभों को पुष्टि हुई। उल्लेखनीय है कि डैले मिर्च को फायर बॉल मिर्च या डैले खुरसानी के नाम से भी जाना जाता है। यह मिर्च अपने तीखेपन, चमकीले लाल रंग और उच्च पोषण मूल्य के लिए प्रसिद्ध है, जो विटामिन ए, सी और ई के साथ-साथ पोटेशियम से भरपूर है।

सराहना

► न्यायाधीश ने पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से अपने पास उपलब्ध सभी सामग्री को सार्वजनिक डोमेन में रखा

जीआई-टैग वाली डैले मिर्च के निर्यात को सुगम बनाया

टीम एक्शन इंडिया नई दिल्ली। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने सिक्किम से सोलोमन द्वीप तक जीआई-टैग वाली डैले मिर्च की पहली खेप का सफलतापूर्वक निर्यात किया है। जीआई-टैग वाली 15,000 किलोग्राम डैले मिर्च के निर्यात से सिक्किम में किसानों की आय में वृद्धि हुई है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने सोमवार को एक बयान में बताया कि सिक्किम से सोलोमन द्वीप तक जीआई-टैग वाली डैले मिर्च की पहली खेप का एपीडा ने सफलतापूर्वक निर्यात



किया है। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि वैश्विक जैविक कृषि बाजार में भारत की बढ़ती प्रमुखता को निहित करती है और पूर्वोत्तर क्षेत्र से प्रीमियम उत्पादों की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय मांग को उजागर करती है। खरीद के संदर्भ में

वृद्धि हुई

► जीआई-टैग वाली 15,000 किलोग्राम डैले मिर्च के निर्यात से सिक्किम में किसानों की आय में वृद्धि हुई

अपने व्यापक नेटवर्क के जरिए दक्षिण सिक्किम के किसानों और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) से लगभग 15,000 किलोग्राम ताजा डैले मिर्च प्राप्त की, जिसमें टिकटम और तारकू क्षेत्र शामिल हैं। इस खेप ने

निर्देश जारी

सैनी ने 2025-26 के लिए गेहू, सरसों, जौ, चना, मसूर व सूरजमुखी की खरीद करने वाली सभी चारों खरीद एजेंसियों के अधिकारियों को निर्देश दिए

रबी की फसलों की खरीद के लिए एजेंसियां कर लें पूरी तैयारियां: सैनी

टीम एक्शन इंडिया चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नयब सिंह सैनी ने रबी विपणन सीजन 2025-26 के लिए गेहू, सरसों, जौ, चना, मसूर व सूरजमुखी की खरीद करने वाली सभी चारों खरीद एजेंसियों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे समय रहते सभी आवश्यक प्रबंध पूरे कर लें, ताकि किसानों को मंडियों में फसले बेचने में दिक्कत न आए। इस बार गेहूं की खेप पैदावार होने का अनुमान है। इसलिए मंडियों में गेहूं खरीद के लिए पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं। मुख्यमंत्री ने मार्केटिंग बोर्ड के



अधिकारियों को निर्देश दिए की भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर मंडियों में खाली पड़े स्थानों पर बड़े शैडों का निर्माण किया जाए। मुख्यमंत्री नयब सिंह

बैठक

► एजेंसियों ने गेहूं खरीद का 75 लाख मीट्रिक टन रखा है लक्ष्य, मंडियों में खाली स्थानों में बड़े शैडों का करवाया जाए

रहे थे। बैठक में मुख्यमंत्री को इस बात से अवगत करवाया कि रबी की फसलों की खाद्य, आपूर्ति नागरिक उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा 30 प्रतिशत, हैफेड द्वारा 40 प्रतिशत, हरियाणा राज्य भंडारण निगम द्वारा 20 प्रतिशत तथा

भारतीय खाद्य निगम द्वारा 10 प्रतिशत की खरीद की जानी है। इस बार एजेंसियों ने गेहूं खरीद का लक्ष्य 75 लाख मीट्रिक टन रखा है। सरसों की खरीद 15 मार्च से और मसूर की खरीद 20 मार्च से आरंभ हो चुकी है। यह खरीद एक मई तक चलेगी। गेहूं, जौ और चने की खरीद भी एक अप्रैल से आरंभ की जाएगी जबकि सूरजमुखी की खरीद 1 जून से आरंभ होगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर रबी फसलों की खरीद अवधि को 15 से 20 दिन जारी रखने का कार्यक्रम बनाया जाए।

मिनी सचिवालय फतेहपुर का 90 प्रतिशत कार्य पूरा, मई मे जनता को होगा समर्पित

लक्ष्य

►जुलाई 2022 मे भाजपा ने रखी थी आधारशिला, अगस्त 2024 मे कार्य पुरा होने का रखा था लक्ष्य

टीम एक्शन इंडिया

विजय समयाल

कांगडा: जिला कांगडा की विधानसभा फतेहपुर में फतेहपुर -भटौली मार्ग पर पुलिस थाना के पास 12 करोड़ पचास लाख की लागत से बनने वाला निमाणाधीन मिनी सचिवालय का निर्माण कार्य 90 प्रतिशत पूरा हो गया है। मई 2025 तक इसे उद्घाटन के बाद जनता को समर्पित कर दिया जा सकता है । जुलाई 2022 मे भाजपा

सरकार ने मिनी सचिवालय की आधारशिला रखी थी और अगस्त 2024 मे इसका कार्य पुरा होना था । मगर 12 करोड़ पचास लाख से बनने वाले इस मिनी सचिवालय का कार्य बजट के अबाव से अधर मे लटका हुआ था । जिस कारण अब यह भवन एक साल देरी से बन रहा है । अब बजट का सार पैसा विभाग को मिल गया चुका है जिसके चलते इसका कार्य युद्ध

मिनी सचिवालय बनने से अब लोगों को एक ही छत के नीचे मिलेगी सारी सुविधा जिस तरह सचिवालय में सभी विभागों के काम एक ही छत के नीचे होते हैं, उसी तरह मिनी सचिवालय फतेहपुर में भी लोगों को यह सुविधा मिलेगी। मिनी सचिवालय मे एसडीएम, तहसील, डीएसपी के साथ ही अन्य महत्वपूर्ण विभागों के कार्यालय

होंगे । ऐसे में लोगों का डबल फायदा हो जाएगा। इसमें में एसडीएम और डीएसपी कार्यालय के अलावा तहसील, ट्रेजरी विभागों के कार्यालय होंगे। लगभग 63 ग्राम पंचायतों को होगा इसका फायदा होगा । लोगों को अपने काम करवाने के लिए अलग अलग जगहो पर नहीं भटकना पड़ेगा । लोक निर्माण विभाग मण्डल फतेहपुर के अधिषाशी अभियन्ता विनय कुमार

का कहना है कि मिनी सचिवालय का निर्माण तेजी से हो रहा है। एक ही छत के नीचे सभी कार्यलय होंगे। इससे लोगों को बहुत फायदा होगा। करीब 12 करोड़ पच्चास लाख की लागत से यह भवन बन रहा है जिसे मई तक जनता को समर्पित कर दिया जाएगा अब जल्द ही मिनी सचिवालय जनता को समर्पित कर दिया जाएगा । लोगों को कार्या करवाने के लिए दूर दूर अलग अलग कार्यलय मे नहीं जाना पडा करेगा । सरकार द्वारा बजट विभाग को मुहैया करबा दिया गया था मिनी सचिवालय का काम अब लग भग पुरा होने वाला है । भाजपा सरकार ने चुनावो को देखते हुए विना बजट की सैपल को संख्या में बढ़ीतरी घोषणा की थी



अनुमति के खाद्य एवं पेय पदार्थ बेचने की अनुमति नहीं है, जो बिना अनुमति के कार्य करेगा उसके खिलाफ कानूनी करवाई की जाएगी।

उपायुक्त ने कहा कि दूध, पनीर, मिठाईयों, फल-सब्जियों की चैकिंग निरंतर फीलड स्टाफ करे। इसके साथ ही रिपोर्ट तुरंत संबंधित विभाग को प्रेषित करें। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत कारवाई की जाएगी। अनुपम कश्यप ने कहा कि होटल रजिोर्ट में होने वाली शादी या अन्य बड़े समारोह के

दौरान खाने के सैपल लिए जाएंगे ताकि खाने की गुणवता पर निगरानी रखी जाए। उन्होंने कहा कि फूड प्वाइजनिंग के मामले ऐसे बड़े आयोजन में होने की संभावना रहती है। उन्होंने कहा कि शिमला शहर के साथ सटे छोटे बाजारों में भी चैकिंग करने के लिए फीलड स्टाफ जाएगा। स्कूलों के आसपास स्थित दुकानों में प्राथमिकता के आधार पर चैकिंग की जाएगी। उपायुक्त ने आम जनता से अपील की है कि खाद्य वस्तुओं में जरा भी खामी पाए जाने पर प्रशासन के ध्यान में लाएं।

न्यूज फ्लैश

हिमाचल डायमंड स्टेटस अवॉर्ड से सम्मानित : प्रेम कौशल

टीम एक्शन इंडिया

विवेकानंद वशिष्ठ

हिमाचल: हिमाचल प्रदेश को प्रगति के लिए डायमंड स्टेटस अवॉर्ड से सम्मानित किया जाना बेहद गौरव की बात है और प्रदेश को मिले इस सम्मान से यह साबित हो गया कि कांग्रेस की सरकार संजीदगी और बचनबद्धता से प्रदेश को प्रगति पथ पर आगे ले जाने का कार्य कर रही है। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने जारी ब्यान में कहा कि डायमंड स्टेटस मिलने से सरकार के खिलाफ भाजपा नेताओं के दुष्प्रचार की हकीकत भी जनता के सामने उजागर हुई है। उन्होंने कहा कि अनेक कठिनाइयों तथा खराब अर्थव्यवस्था और केंद्र सरकार के उपेक्षा पूर्ण रवैए के बावजूद कांग्रेस सरकार हर वर्ग को राहत देने के साथ साथ प्रदेश को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने की दिशा में भी सार्थक कार्य कर रही है। कौशल ने कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने ही प्रदेश को पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में विकास मॉडल राज्य के रूप में स्थापित करने का कार्य किया है।

त्रिलोकपुर मेलें के दौरान आग्नेयास्त्र, मांस-मछली व तूड़ी ढुलाई वाले वाहनों पर रहेगा प्रतिबंध : जिला दंडाधिकारी

टीम एक्शन इंडिया

एसपी जैरथ

नाहन: जिला दण्डाधिकारी सिरमौर एल.आर.वर्मा ने आज यह आदेश जारी करते हुए बताया कि 30 मार्च से 12 अप्रैल, 2025 तक चलने वाले श्री महाभाया बाला सुंदरी चैत्र नवरात्र मेला त्रिलोकपुर के दौरान कालाअंब पुलिस स्टेशन और मेला क्षेत्र की सीमाओं में किसी भी प्रकार के आग्नेयास्त्र, घातक हथियार व विस्फोटक सामग्री आदि लाने ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने यह भी आदेश जारी किए हैं कि मेला अवधि के दौरान कोई भी तीर्थयात्री मंदिर में नारियल नहीं चढ़ाएगा तथा मेला क्षेत्र में शराब लेकर/ पीकर कोई भी गैर कानूनी गतिविधि नहीं करेगा। जिला दण्डाधिकारी ने आदेश जारी किए हैं कि कालाअंब से त्रिलोकपुर रोड पर 30 मार्च से 12 अप्रैल, 2025 तक यातायात व्यवस्था को सूचारू रूप से बनाए रखने हेतु प्रातः 6 बजे से रात्री 10 बजे तक उद्योगों में प्रयुक्त होने वाले तूड़ी अथवा भूस आदि से लदे ट्रक व ट्रैक्टर चलाने पर प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने मेला अवधि के दौरान धार्मिक भावना एवं आस्था के महेनजर यह आदेश जारी किए हैं कि सम्पूर्ण मेला क्षेत्र त्रिलोकपुर में मांस व मछली इत्यादि की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा ताकि मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं में किसी प्रकार का जनाक्रोश उत्पन्न न हो। उन्होंने बताया कि कालाअंब से त्रिलोकपुर सडक के साथ लगती मांस व मछली की दुकानों में विक्रेताओं को केवल दुकान के अंदर ही (पर्दे में) मांस व मछली का विक्रय करना होगा। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।

शिमला एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला, पायलट को लगानी पड़ी इमरजेंसी ब्रेक

शिमला/टीम एक्शन इंडिया

राजधानी शिमला के जुबड़हट्टी हवाई अड्डे पर सोमवार सुबह एक बड़ा हादसा टल गया। दिल्ली से शिमला आ रही एलायंस एयर की एटीआर फ्लाइट लैंडिंग के दौरान रनवे पर संतुलन बनाने में मुश्किल में आ गई। विमान ने अपेक्षा से आगे लैंड किया जिससे पायलट को अंतिम छोर पर इमरजेंसी ब्रेक लगाना पड़ा। इस विमान में प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) समेत कई अन्य यात्री सवार थे। इमरजेंसी ब्रेक लगने के दौरान विमान में बैठे यात्रियों में घबराहट का माहौल बन गया। हालांकि पायलट और क्रू मेंबर्स की सूझबूझ से विमान को सुरक्षित रोका जा सका। इस घटना के बाद एलायंस एयर ने तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए विमान को आगे धर्मशाला न भेजने का फैसला किया और शेष उड़ानों को भी रद्द कर दिया।

लाख रेनबो ट्राउट मत्स्य बीज का स्थानांतरण मत्स्य विभाग उत्तराखंड उत्तरकाशी को किया गया

टीम एक्शन इंडिया

श्याम कुल्वी

कुल्लू : जिला कुल्लू के फोजल क्षेत्र में कार्यशील रेनबो ट्राउट मत्स्य कृषक सरला नेगी द्वारा अपनी हेचरी से 1 लाख रेनबो ट्राउट मत्स्य बीज का स्थानांतरण मत्स्य विभाग उत्तराखंड उत्तरकाशी को किया गया पूरब में भी एक लाख अंडों का स्थानांतरण उत्तराखंड मत्स्य विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश में कार्यशील मत्स्य पालकों से लिया गया था । निदेशक और प्रारक्षी मत्स्य विभाग विवेक चंदेल ने बताया कि विभाग निरंतर मत्स्य पालकों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए प्रयासरत है और जिला कुल्लू को एक ट्राउट हब के रूप में विकसित करने के लिए



निरंतर प्रयासरत है आने वाले समय में जैसा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत नए ट्राउट रिसेवज का निर्माण चला हुआ है। विभाग इसी कड़ी में मत्स्य बीज प्रजनन क्षमता को बढ़ाने के लिए कार्यशील है ताकि आने वाले समय में मत्स्य बीज में हम न केवल पूर्ण रूप से स्वावलंबी हो अपितु प्रदेश के बाहर कार्यशील मत्स्य पालकों को भी इसी भांति और ज्यादा सीड दे कर सकें।

राज्यस्तरीय लघु शिवरात्रि मेला के जोगिंद्रनगर के लिए कलाकारों के ऑडिशन 27, 28 व 29 को

टीम एक्शन इंडिया

संगराय

जोगिंद्रनगर : एक से पांच अप्रैल तक मनाए जाने वाले राज्य स्तरीय लघु शिवरात्रि मेला जोगिंद्रनगर की चार सांस्कृतिक संध्याओं में प्रस्तुति देने के लिए कलाकारों के ऑडिशन 27, 28 व 29 मार्च को निर्धारित किये गए हैं। यह ऑडिशन मिनी सचिवालय परिसर के सभागार में प्रातः 10 बजे से सायं 3 बजे तक लिए जाएंगे। इस बारे जानकारी देते हुए मेला समिति अध्यक्ष एवं एसडीएम मनीश चौधरी ने बताया कि राज्य



स्तरीय लघु शिवरात्रि मेला जोगिंद्रनगर में चार सांस्कृतिक संध्याओं में प्रस्तुति देने के इच्छुक कलाकार 27, 28 व 29 मार्च को ऑडिशन में भाग ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि 27 मार्च

पनोग पंचायत की डिल्ली सडक की हुई सफल पासिंग

टीम एक्शन इंडिया

चमन शर्मा

शिमला: कोटखाई क्षेत्र की ग्राम पंचायत पनोग की डिल्ली सडक सम्पर्क मार्ग की सफलतापूर्वक पासिंग होने पर पंचायत वासियों ने शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर का आभार व्यक्त किया है। लाभार्थियों ने संयुक्त ब्यान जारी करते हुए कहा कि शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के अथक प्रयासों से डिल्ली सडक सम्पर्क मार्ग की सफल पासिंग सम्भव हो पाई है। गौरतलब है कि उप चुनाव के बाद जुब्बल-नावर-कोटखाई में अब तक रिकॉर्ड 112 सडकें

को जोगिन्दर नगर व पधर उपमंडल, 28 मार्च को जिला मंडी तथा कांगडा जिला के बैजनाथ व पालमपुर उपमंडल तथा 29 मार्च को प्रदेश के अन्य जिलों के कलाकार ऑडिशन में भाग ले सकते हैं। यह ऑडिशन मिनी सचिवालय परिसर के सभागार में प्रातः 10 बजे से सायं 3 बजे तक लिए जाएंगे। एसडीएम ने बताया कि कलाकारों के ऑडिशन लेने के लिए तहसीलदार जोगिन्दर नगर के संयोजन में एक समिति गठित की गई है।

पनोग पंचायत की डिल्ली सडक की हुई सफल पासिंग

तथा कांग्रेस सरकार के गठन के बाद 92 सडकों की सफल पासिंग हो चुकी हैं। इसके विपरीत पूर्व भाजपा सरकार के चार वर्ष के कार्यकाल में पूरे विधानसभा क्षेत्र में मात्र 5 सडकों की ही



पासिंग करवा पाई इसके साथ ही क्षेत्र में सडकों की दुर्गति बनी रही।

शहीद दिवस के अवसर पर कवि गोष्ठी एवं परिचर्चा आयोजित

टीम एक्शन इंडिया

हामिद

चंबा: शहीद दिवस के अवसर पर भाषा एवं संस्कृति विभाग , नेता जी सुभाष चंद्र बोस- जयन्ती आयोजन समिति के संयुक्त तत्वावधान में ढुंड्यारा बंगला में कवि गोष्ठी और परिचर्चा का आयोजन किया गया। जिला भाषा अधिकारी तुकेश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि देश के महान शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए गोष्ठी का शुभारंभ किया गया। हिमाचल प्रदेश की समृद्ध- सांस्कृतिक धरोहर तथा साहित्यिक परंपराएं परिचर्चा का हिस्सा रहीं। वरिष्ठ, नवोदित, बाल-कवियों ने अपनी रचनाओं



का पाठ कर गोष्ठी को सफल बनाया । बाल कवि आदिल, तन्वी यशबनी, यसमाश्री ने काव्य पाठ कर अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित किया। कवि करुण कुमार, थे वीर अनोखे अहड़ड से वो अनूप

जन्म सिद्ध अधिकार है भूपेंद्र सिंह जसरोटिया, - खण्डा साही घुलदी चम्ब्याली मुकी गया पाणी सुनो चम्बे दी कहाणी सुभाष साहिल, बचपन यौवन खुशियाँ मिश्रा श्वाश लिखे रणजीत ठाकुर आग लगी वृक्ष को उड़ जा पछिला अशोक दर्द, सब कुछ भूल कर जो फंदे पर झूल गए-पिछलते नहीं पथर आंसू बहाने से- मैं कविए दी लाडी अडियो मौनिका उपासना पुष्प, कई साल हो गए आजादी को तुमसे गुजर कर जो हवा आ रही अमित भारद्वाज धुंधले से किस्से वक्त की दीवारों से हो गए अभिषेक आदि रचनाओं का पाठ किया। कवियों ने मानवीय संबंधों, समाज के ताने-बाने,

उलझते रिशतों और प्रकृति के विविध पहलुओं पर आधारित रचनाओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। कवि सम्मेलन के दौरान हिमाचल प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर और समाज के विकास में साहित्य के योगदान पर विशेष चर्चा की गई। इस दौरान वक्ताओं ने हिमाचल के सांस्कृतिक तथा सामाजिक सौंदर्य तथा साहित्य के प्राकृतिक महत्व पर अपने विचार साझा किए। मंच का संचालन जगजीत आजाद ने किया। इस अवसर पर केप्टन जैसी राम शर्मा, तरुण नशकर, ऋतु कोशिक विशेष तौर पर उपस्थित रहे।

क्षय रोग दिवस पर जागरूकता रैली का आयोजन

टीम एक्शन इंडिया

खेमचंद शास्त्री

मंडी: विश्व क्षयरोग दिवस के अवसर पर आज क्षेत्रीय अस्पताल मंडी में जिला स्तरीय क्षय रोग दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राजकीय नर्सिंग विद्यालय मंडी की प्रशिक्षु छात्राओं तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों ने भाग लिया । इस अवसर पर जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. दिनेश ठाकुर ने क्षेत्रीय अस्पताल मंडी के परिसर से एक जागरूकता रैली को हरी झंडी



दिखाकर रवाना किया। यह रैली अस्पताल से सेरी मंच तक निकाली गई, जिसमें प्रशिक्षुओं ने स्लोगन व नारों के माध्यम से क्षय रोग से बचाव संबंधित जानकारी प्रदान की।

आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज है: सीएम योगी

सुरक्षा, सुशासन, समृद्धि और सनातन संस्कृति के क्षेत्र में प्रदेश की जो पहचान बनी है उसका एहसास पूरा भारत कर रहा है- सीएम योगी

टीम एक्शन इंडिया लखनऊ। सरकार के 8 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लोकभवन में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में अपनी सरकार के विकास कार्यों का विस्तृत खाका प्रस्तुत किया। इस दौरान 8 वर्षों में यूपी में सरकार के कामकाज पर "एक झलक" रिपोर्ट कार्ड डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई और पुस्तिका का विमोचन किया गया। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और 25 करोड़ प्रदेशवासियों के समवेत प्रयास से आज यह उत्तर प्रदेश, भारत के 'श्रम शक्ति पुंज' से अर्थ शक्ति पुंज' बनने की ओर अग्रसर है। उत्तर प्रदेश वही है,



लेकिन बोते 8 वर्षों परसेशन पूरी तरह से बदल चुका है। सुरक्षा, सुशासन, समृद्धि और सनातन संस्कृति के क्षेत्र में जो पहचान बनी है उसका एहसास उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरा भारत कर रहा है। उन्होंने कहा कि 8 वर्ष पहले बीमारू राज्य की पहचान रखने वाला उत्तर प्रदेश आज देश की

अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बन चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेरणादायी मार्गदर्शन और उनके विजनरी नेतृत्व में सेवा, सुरक्षा और सुशासन के 8 वर्ष पूरे हुए हैं। उन्होंने 25 करोड़ प्रदेशवासियों को 8 वर्ष की इस शानदार यात्रा के लिए बधाई दी

विस्तृत खाका

▶▶ लोकभवन में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में अपनी सरकार के विकास कार्यों का विस्तृत खाका प्रस्तुत किया

और कहा कि डबल इंजन सरकार ने हर क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन किया है। सीएम योगी ने कहा कि आगामी 25, 26 और 27 मार्च को प्रत्येक जिला मुख्यालय पर तीन दिवसीय 'विकास उत्सव' आयोजित होगा, जिसमें अन्नदाता किसानों, युवाओं, मातृशक्ति, हस्तशिल्पियों और उद्यमियों को सम्मानित किया

जाएगा। यहां केंद्र सरकार के 10 व प्रदेश के 8 वर्षों की विकास यात्रा को जनता के समक्ष रखा जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। यूपी नंबर दो की अर्थव्यवस्था है और जल्द नंबर एक बनेगा। उन्होंने पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और मंत्रिमंडल के सहयोगियों और एनडीए के सभी घटक दलों का आभार जताया। सीएम योगी ने कहा कि यह 8 वर्ष की शानदार यात्रा टीम भावना, स्केल, स्किल और स्पीड का परिणाम है। 8 वर्ष पहले पहचान की संकट से जूझ रहा था उत्तर प्रदेश-

सीएम योगी

सीएम योगी ने 2017 से पहले की स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि 8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की पहचान संकट में थी। किसान आत्महत्या कर रहे थे, युवा अपनी पहचान के मोहताज थे, बेटियां और व्यापारी असुरक्षित थे। दंगों और अराजकता ने अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया था। उन्होंने कहा कि उस समय उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य माना जाता था और इसे देश के विकास में बाधक समझा जाता था। लेकिन 8 वर्षों में डबल इंजन सरकार ने इस परसेशन को पूरी तरह बदल दिया। आज उत्तर प्रदेश देश के विकास का ब्रेकथ्रू बनकर हर सेक्टर में आगे बढ़ रहा है।

पुलिस को प्रदेश की सुरक्षा में लगाया जाए : जयराम

टीम एक्शन इंडिया

शिमला। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश में बढ़ते अपराध और पुलिस की कार्यवाई में ढिलाई को लेकर सरकार पर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराध लगातार बेकाबू हो चुका है और पुलिस अपने कर्तव्यों से भटककर राजनीतिक मामलों में उलझी हुई है। जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री से निवेदन किया कि पुलिस को प्रदेश की सुरक्षा में लगाया जाए न कि विपक्षियों की सीआईडी जांच करने में। उन्होंने विमल नेगी के मामले का हवाला देते हुए कहा कि पुलिस ने शुरू में उनकी खोज में कोई रुचि नहीं दिखाई और परिजनों ने इनाम घोषित किया तब जाकर पुलिस सक्रिय हुई। साथ ही पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट ने मामले को और संदिग्ध बना दिया। नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश में



बढ़ते अपराधों का जिक्र करते हुए कहा कि नए साल में 21 हत्याएं और 14 नशे से जुड़ी मौतें हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार नशे के मामलों में कमी का झूठा दावा कर रही है, जबकि स्थिति गंभीर है। उन्होंने मंडी में ढाबा संचालक से हुई डकैती और पुलिस की लापरवाही का भी जिक्र किया। इसके साथ ही सुंदरनगर में खालिस्तान समर्थकों के नारे लगाने का मामला उठाया।

तुष्टिकरण की ठेकेदार कांग्रेस संविधान बदलने पर आमादा : अनुराग सिंह

टीम एक्शन इंडिया शिमला। पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने संसद में कर्नाटक में मुस्लिमों के लिए आरक्षण को लेकर कांग्रेस सरकार पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार संविधान में बदलाव कर भारत को गांधी-पटेल का देश न बना कर जिन्ना का मुस्क बनाने की कोशिश कर रही है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, ह्मकायस जो गली-गांव, मोहल्ले में संविधान का राग अलापती है, आज वही पार्टी कर्नाटक में सिर्फ तुष्टिकरण के उद्देश्य से मुसलमानों को सरकारी ठेकों में आरक्षण देने जा रही है। यह संविधान में बदलाव का



प्रयास है। धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, यह बात हर व्यक्ति जानता है, लेकिन कांग्रेस अब मुस्लिमपरस्ती में मशगूल हो गई है और मुस्लिम लीग बनने की ओर अग्रसर है। वे गांधी और पटेल के देश को जिन्ना का मुस्क बनाने पर आमादा हैं, लेकिन हम चुप नहीं रहेंगे और कांग्रेस को उसके मंसूबे में सफल नहीं होने देंगे। उन्होंने

प्रतिक्रिया

▶▶ अनुराग ने संसद में कर्नाटक में मुस्लिमों के लिए आरक्षण को लेकर कांग्रेस सरकार पर कड़ी प्रतिक्रिया दी

आगे कहा, ह्मविपक्ष के नेता हमारे पूर्वजों, नायकों और देश की गौरवमयी छवि को अपमानित करने में व्यस्त हैं। आज देश यह सवाल पूछ रहा है कि चंद वोटों के लिए आपने अपने स्वाभिमान को क्यों बेच दिया? दुनिया जहां से कहां पहुंच गई है, लेकिन भारत में कुछ लोग अभी भी 17वीं सदी की सोच में जी रहे हैं।

केदारनाथ पैदल मार्ग पर बर्फ की संकरी घाटी से आगे बढ़ेंगे श्रद्धालु

टीम एक्शन इंडिया

रुद्रप्रयाग। 2 मई से शुरू होने वाली केदारनाथ यात्रा में बाबा केदार के भक्त बर्फ की संकरी घाटी से होकर धाम पहुंचेंगे। गौरीकुंड-केदारनाथ पैदल मार्ग पर रामबाड़ा से लिनचोली के बीच पसर शिवालकाय हिमखंडों को काटकर लोक निर्माण विभाग के मजदूर रास्ता तैयार करने में जुटे हैं। इस वर्ष फरवरी पहले सप्ताह और इस माह के पहले व दूसरे सप्ताह में केदारनाथ सहित पैदल मार्ग तक भारी बर्फबारी हुई थी। इन दिनों भी केदारनाथ में तीन फीट से अधिक बर्फ जमा है। वहीं, गौरीकुंड-केदारनाथ पैदल मार्ग पर रामबाड़ा से केदारनाथ तक बर्फ के कारण पैदल आवाजाही संभव नहीं है। यहां बोते 14 मार्च से लोक

निर्माण विभाग के 70 से अधिक मजदूर बर्फ को काटकर रास्ता बनाने में जुटे हैं। 11 दिनों में लगभग ढाई किमी हिस्से में बर्फ साफ कर आवाजाही के लिए रास्ता तैयार हो चुका है। इन दिनों मजदूर थारू हिमखंड को काटने में जुटे हैं। यहां पर लगभग 20 फीट ऊंचे हिमखंड को काटकर ढाई फीट चौड़ा रास्ता बनाया जा रहा है। बर्फ काटने से यहां गहरी व संकरी घाटी सी बन गई है। यहां बर्फ खिसकने का खतरा बना है। लॉनिवि के अधिशासी अभियंता विनय झिक्वांण ने बताया कि मौसम अनुकूल नहीं होने के बाद भी बर्फ सफाई का कार्य ज़ोरों पर चल रहा है। हिमखंड जोन पर आने वाले दिनों में रास्ते की चौड़ाई बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा।

टीम एक्शन इंडिया

शिमला। हिमाचल पावर कोर्पोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत का मामला सोमवार को विधानसभा में फिर उठा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विपक्षी दल भाजपा पर आरोप लगाया है कि वह इंजीनियर विमल नेगी की मौत के मामले में राजनीतिक लाभ लेने के लिए सीबीआई जांच की मांग कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के नेता सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए नेगी के परिवार से मिलने पहुंचे थे लेकिन उनके इरादे पूरे नहीं हो सके। उन्होंने भाजपा को इस मामले में राजनीति करने से बचने की सलाह दी और कहा कि सरकार पहले ही 15 दिनों के भीतर इस मामले की उच्च स्तरीय



जांच के आदेश दे चुकी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो भी दोषी होगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री सोमवार को विधानसभा में पुलिस और कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष द्वारा लाए गए कटौती प्रस्ताव पर जवाब दे रहे थे। विपक्ष की गैरमौजूदगी में सदन ने प्रस्तावों को नामंजूर कर दिया और बजट मांग को मंजूरी दे दी। विपक्ष पर सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा आखिर सिर्फ सीबीआई जांच की मांग क्यों कर रही है? उन्होंने

उच्च स्तरीय

▶▶ चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत का मामला सोमवार को विधानसभा में फिर उठा

आरोप लगाया कि सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियां भाजपा के नियंत्रण में हैं और इनका इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए किया जाता है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में इन एजेंसियों की छापमारी पहले भी होती रही है, जैसे नांदेन में हुई थी। उन्होंने कहा कि भाजपा को इस तरह की जांच एजेंसियों का राजनीतिक लाभ नहीं उठाना चाहिए।

उत्तराखंड सरकार अवैध मदरसों की फंडिंग की करेगी जांच

टीम एक्शन इंडिया देहरादून। उत्तराखंड की धामी सरकार अवैध रूप से संचालित मदरसों पर कार्यवाई के बाद अब उनकी फंडिंग की गहन जांच करने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रदेश में अवैध मदरसों, मजार और अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाई लगातार जारी रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध रूप से बड़े पैमाने पर मदरसों का संचालन गंभीर विषय है जिसकी जांच के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इसकी रिपोर्ट अधिकारी सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपेंगे। प्रदेश में अवैध मदरसों के खिलाफ बड़े



स्तर पर कार्यवाई की जा रही है। अब तक पूरे प्रदेश में 136 मदरसों को कागजात पूरे न होने पर सील किया जा चुका है, जबकि रिपोर्ट में पूरे प्रदेश में 500 से अधिक अवैध मदरसे संचालित होने की बात कही जा रही है। बताया गया है कि राज्य

फंडिंग

▶▶ प्रदेश में अवैध मदरसों, मजार और अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाई लगातार जारी रहेगी: मुख्यमंत्री

में करीब 450 पंजीकृत मदरसे हैं, जो शासन को अपने दस्तावेज, बैंक खाते और आय-व्यय का पूरा ब्योरा देते हैं लेकिन दूसरी ओर 500 से अधिक मदरसे बिना किसी मान्यता के संचालित हो रहे हैं। इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का सत्यापन और आर्थिक स्रोतों की जांच के

लिए शासन ने जिला प्रशासन को सख्त निर्देश जारी किए हैं। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि इन अवैध मदरसों को किस स्रोत से धन मिल रहा है और उसका उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है। सीमा से सटे क्षेत्रों में खुल रहे अवैध मदरसे पिछले कुछ समय में उत्तर प्रदेश से सटे कस्बों जैसे जसपुर, बाजपुर, किच्छा, काशीपुर, रुद्रपुर, गदरपुर, पछवादा और हरिद्वार जिले में बिना पंजीकरण के कई मदरसे खुलने की सूचना मिली है। सरकार इन मदरसों के स्रोतों और उद्देश्यों की जांच कर आवश्यक कार्यवाई कर रही है।

शिमला में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे जल रक्षक, नियमितिकरण नीति में संशोधन की मांग

टीम एक्शन इंडिया

शिमला। हिमाचल प्रदेश में जल रक्षकों ने सोमवार को अपनी मांगों को लेकर शिमला के चौड़ा मैदान में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदेशभर से आए जल रक्षकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नियमितिकरण नीति में संशोधन की मांग उठाई। जल रक्षक संघ ने सरकार को चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता, तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। जल रक्षक

जोरदार प्रदर्शन

▶▶ जल रक्षकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नियमितिकरण नीति में संशोधन की मांग उठाई

संघ के प्रदेशाध्यक्ष रूप लाल ने बताया कि प्रदेशभर में करीब नौ हजार जल रक्षक सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उनके वेतन और

स्थायीकरण को लेकर कोई ठोस नीति नहीं बनाई गई है। उन्होंने बताया कि हाल ही में सरकार ने उनका वेतन केवल 300 रुपये बढ़ाकर 5,600 रुपये किया है, जो उनकी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए बेहद कम है। संघ की प्रमुख मांग है कि जल रक्षकों की नियमितिकरण अवधि को 12 वर्षों से घटाकर 7 वर्ष किया जाए और उन्हें पूर्ण रूप से जल शक्ति विभाग में शामिल किया जाए।

शिक्षा क्रांति निःशुल्क शिक्षा से संवार रहे बच्चों के भविष्य, बीते आठ वर्षों में सर्वोदय विद्यालयों की संख्या बढ़कर हुई 120

गरीब छात्रों के लिए वरदान बने सर्वोदय विद्यालय

टीम एक्शन इंडिया लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश के शिक्षा तंत्र में आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिल रहा है। गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के संकल्प के तहत संचालित जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय प्रदेश में शिक्षा के एक आदर्श मॉडल के रूप में विद्यापित हो रहे हैं। योगी सरकार के प्रयासों से 2017 से पहले जहां मात्र 93 सर्वोदय विद्यालय संचालित थे, वहीं 2024-25 तक इनकी संख्या बढ़कर 120 हो गई है। इन विद्यालयों में से 100 वर्तमान में



संचालित हैं, जिनमें 70 बालक विद्यालय और 30 बालिका विद्यालय शामिल हैं। इस योजना के तहत हर विद्यालय में 490 छात्रों की क्षमता निर्धारित की गई है, जिससे हजारों छात्रों को लाभ मिल रहा है। राष्ट्रीय प्रेरणा तथा सामाजिक

सद्भावना को आगे बढ़ाने का उत्कृष्ट केंद्र है सर्वोदय विद्यालय- योगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमेशा शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण का सबसे प्रभावी माध्यम बताया है। उनके नेतृत्व में सरकार न केवल

विद्यालयों की संख्या बढ़ा रही है, बल्कि उनमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित कर रही है। यह योजना प्रदेश में गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें मुख्यधारा में लाने का सशक्त माध्यम बन रही है। सीएम ने प्रदेश में संचालित जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय में और सुविधाएं बढ़ाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मानना है कि प्रदेश भर में ये विद्यालय अपनी पूरी क्षमता के साथ संचालित किए जाने चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता को और बढ़ाएं।

H.O: Action Balaji House, Majlis Park, Near Rakesh Bhardwaj Chowk, Delhi- 110033

B.O: Shakti Complex, 6/18, Main Gt Road, Samaypur Industrial Area, Delhi -110042



9999889104, 8447314925